प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 -09 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांकः मार्च 5 , 2024

विषयः क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9126/2023 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 20.12.2023 के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदय,

क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9126/2023 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 14.09.2023 के अनुपालन में सम्मन/वारण्ट के तामीला की व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-एचसी-100/छः-पु0-9-2023 दिनांकित 14.10.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** तथा डीजी परिपत्र संख्या-40/2023 दिनांकित 10.10.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये निर्देशों को शपथपत्र के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 शासन तथा इस मुख्यालय स्तर से निर्गत उपरोक्त निर्देशों पर विचार करते हुये क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9126/2023 उपरोक्त में आदेश दिनांकित 20.12.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** पारित किया गया, जिसमें इन निर्देशों को सम्यक एवं उपयोगी पाते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें न्यायिक निर्णय का अंश बनाया गया है तथा यह निर्देशित किया गया है कि इन निर्देशों का अनुपालन न्यायिक आदेश के रूप में किया जाय।

अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या-107/PSAAG /HC/ALLD दिनांकित 17.02.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा न्यायिक निर्णय के मुख्य अनुपालन योग्य विन्दुओं को सारांश रूप में निम्नवत अंकित करते हुये प्रेषित किया है तथा इन निर्देशों का अनुपालन न्यायिक आदेश के रूप में सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है –

1. Additional Director General (Prosecution) is directed to issue a direction regarding maintainability of witness register with 'Court Moharrir', in which name and address, mobile number, Aadhar number of every prosecution witnesses will be mentioned and a direction is also issued to insert a column in the 'Pairavi Register' of concerned Pairokar of Police Station.

2. District Nodal Officer will ensure that the Public Prosecutor and concerned 'Court Moharrir' will have access to process register of learned trial courts so that police station/ summon cell process register could be matched. A direction to learned trial courts to this effect, by Hon'ble High court, will be required.

.....2

3. Designation, mobile number of police official who received the court process will be clearly mentioned in the column of process register of learned trial court, so that his responsibility could be fixed.

4. A central register will be prepared for entering processes received from different trial courts in the office of the Nodal Officer and a Desk will be established for sending the summon/ warrants for its execution daily processes will be recorded in central register, policeman will be deployed at the process desk.

5. The service receipt received after service of summons/warrants will be entered in the central register by policeman posted at summon desk and service report will be communicated to the concerned trial court.

6. In compliance with the processes served, the details of the witnesses present and examined in trial courts will also be complied through summon/warrant desk and it will be reviewed from time to time at the competent officer level.

7. Nodal Officers will weekly examine the Summons/warrants execution register.

8. A monthly statement will be prepared in respect of the service of processes and same will be presented before Nodal officer for perusal. The Nodal Officer will warn in writing to subordinate Officers and station in charge who are on laxity and after three consecutive months of laxity, so cause notice will be issued against the subordinate Officers and In-charge of Police Station.

9. At District level Deputy Superintendent of Police/Additional Superintendent of Police and at Police Commissionerate level Assistant Police Commissioners will monitor the service of processes by the concerned police stations under their local jurisdiction and if any laxity will be found Supervisory officers will be accountable.

10. Every Nodal Officer will be responsible for execution of service of processes (summons / warrants/ notices) under their local jurisdiction.

.....3

11. Work of Nodal Officers will be regularly assessed by Additional Director General of Police (Zonal) and Regional Inspector General of Police / Deputy Inspector General of Police in case of any laxity, he will inform the head quarter of Director General of Police.

12. Superintendent of Police will be a Nodal Officer in place of Additional Superintendent of Police.

13. Additional Director General (Prosecution) is directed to issue a direction regarding maintainability of witness register with 'Court Moharrir, in which name and address, mobile number, Aadhar number of every prosecution witnesses will be mentioned and a direction is also issued to insert a column in the 'Pairavi Register of concerned Pairokar of Police Station.

अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांकित 17.02.2024 में साक्षियों का बयान वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कराये जाने की मूलभूत व्यवस्था सभी न्यायालयों में उपलब्ध होने के सम्बन्ध में निम्नवत सूचित किया गया है–

As far as now the Rules for Video Conferencing for Courts in the State of U.P. 2020 have been enforced with effect from 27.11.2020 and the complete paraphernalia and the infrastructure is available in every Court. Now, the Video Conferencing can help the State witnesses also including the Investigating Officers as well as Doctors including other prosecution witnesses at all states of the judicial proceedings and the proceedings conducted by the Court especially when the required person is at any remote point and Coordinator at both the Court point and the remote point has to ensure that in case of application for appearance, evidence and submission through Video Conferencing is moved, the person is duly examined in accordance with the provisions of Rules for Video Conferencing for Courts in the State of U.P. 2020.

Even the orders of the Hon'ble Court are there with specific directions that the facilities of Rules for Video Conferencing for Courts in the State of U.P. 2020 be used to the hilt so that the precious time and machinery of the State Government may be saved and process of prosecution evidence be expedited.

आप सहमत होंगे कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवेचकों एवं औपचारिक साक्षियों का बयान अंकित किये जाने से बहुमूल्य समय एवं संसाधनों की बचत होगी। इस मुख्यालय के पत्र संख्याःडीजी-दस-वि0प्र0-मिस-86/2021 दिनांकित 29.02.2024 के क्रम में प्रत्येक कमिश्नरेट / जनपद हेतु Remote Coordinator (सुदूर समन्वयकर्ता) नियुक्त किये जा चुके हैं, अतः अपर महाधिवक्ता द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव के क्रम में अधिक से अधिक पुलिस साक्षियों का बयान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज कराने का प्रयास किया जाए।

.....4

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.12.2023, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-एचसी-100/छः-पु0-9-2023 दिनांकित 14.10.2023 तथा डीजी परिपत्र संख्या-40/2023 दिनांकित 10.10.2023 का गहनता से अध्ययन करते हुये इनमें अंकित निर्देशों से अपने अधीनस्थों को भलीभाँति परिचित कराते हुये इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उनका यह कृत्य मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आयेगा।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

5.3.24.

(प्रशान्त कुमार)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Annexure No-2

10

महत्वपूर्ण/समयबद्ध/कोर्टकेस

संख्या-एचसी-100/छ:-पु0-9-2023

प्रेषक,

संजय प्रसाद,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2- विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर, 2023

विषय:-विचारण न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन तथा विभिन्न प्रपीड़ात्मक आदेशिकाओं के शीघ्र तामीला तथा निष्पादन संबंधी नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उक्त नीति के समुचित प्रवर्तन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक अपराधी को विधि के न्यायालय द्वारा शीघ्र विचारण के माध्यम से दण्डित कराया जाए। यह तभी संभव होगा जबकि विचारण में साक्षियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इस उद्देश्य से विचारण न्यायालयों में प्रचलित अभियोगों में साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में गृह विभाग के शासनादेश संख्या-यू0ओ0-64/छ:-पु0-9-2022 दिनांक 23.11.2022 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

2. उक्त शासनादेश के माध्यम से यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रचलित अभियोगों में साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय:

i. न्यायालय से प्राप्त किये गये सम्मन (प्रोसेस) का दाखिला तिथवार जनरल डायरी में भी किया जाये। प्रत्येक थाने पर हैड मोहर्रिर द्वारा तारीख पेशी वार सम्मन वारन्ट पंजिका अद्यतन रखी जायेगी ताकि पुलिस थाने पर प्राप्त होने वाले सम्मन / वारन्ट निष्पादनोपरांत न्यायालय में प्रेषित किए जाने में कोई लापरवाही ना हो।

ii. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 62 की मंशा के अनुरूप तामीलशुदा तथा वापस प्राप्त हुए सम्मन की एक प्रति अभियोजन के माध्यम से इस उल्लेख के साथ कि सम्मन तामीलशुदा प्राप्त हुआ है, न्यायालय की पत्रावली में दाखिल की जायेगी।

OATH COMMISSIONER
High Court
14/10/2023

No. 0155544
Date 14-10-2023

iii. अन्य राज्यों के सम्मन/वारन्ट की तामील हेतु नजदीकी राज्यों के सम्मन वारंट की तामील का उत्तरदायित्व निकटवर्ती जिलों को दिया जाए।

iv. तामील के समय संबंधित व्यक्ति का वर्तमान मोबाईल नम्बर का पता लगाया जाए। थानाध्यक्ष द्वारा उस मोबाईल नम्बर से उस व्यक्ति का पता प्राप्त करके तामील कराई जा सकती है। सेवानिवृत्त पुलिस अथवा अन्य शासकीय सेवाओं के सम्मन/वारन्ट प्राप्त होने पर यदि उनके निवास स्थान का पूर्ण पता ज्ञात नहीं हो तो पेंशन विभाग या बैंक अकाउंट का नंबर प्राप्त कर बैंक के माध्यम से पता ज्ञात किया जाए।

v. यदि वारन्ट अदम तामील है तो उद्घोषणा और कुर्की की कार्यवाही आवश्यक रूप से करायी जाए एवं मफरूर की सम्पत्ति की सूची न्यायालय में प्रस्तुत की जाए ताकि धारा 82-83 दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की कार्रवाई पूर्ण कर सम्पत्ति की कुर्की संभव हो सके।

vi. यदि वारन्ट अदम तामील है एवं वारन्टी जमानत पर हो तो जमानत देने वाले व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की जाए तथा आवश्यक हो तो जमानत राशि जब्त कराने हेतु न्यायालय में धारा 456 दं०प्र०सं०, 1973 के तहत प्रार्थना की जाए।

vii. जहाँ लोक अभियोजक द्वारा किसी साक्षी स्थानांतरित पुलिस कर्मी का वर्तमान पता ज्ञात न किया जा पा रहा हो वहाँ ऐसे पुलिसकर्मी का समन स्थानीय पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त पुलिस के स्थापना शाखा के अधिकारी के पास पुलिस मुख्यालय लखनऊ भेजकर उन्हें तामील कराया जाय।

viii. न्यायालय से किसी राजपत्रित अधिकारी को साक्षी के तौर पर तलब किये जाने हेतु तिथि नियत कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि उसे उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके दायित्वों के निर्वहन का समुचित प्रबन्ध करने का अवसर उपलब्ध रहे। यह महत्तम प्रयास हो कि त्यौहारों तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशासन एवं पुलिस को साक्षियों को उपस्थित करने हेतु विवश न किया जाये।

ix. किसी चिकित्सक साक्षी को ऐसे समय पर तलब कराया जाये जबकि उसके पदीय कर्तव्यों पर कम से कम असर पड़ता हो तथा न्यायालय तत्काल उनके बयान अंकित करा सके, साथी ही इन्हें जारी किये जाने वाले सम्मन पर इतना विवरण अवश्य हो कि उन्हें किस मामले में और क्या गवाही देनी है।

3. ज्ञातव्य है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 61 द्वारा न्यायालयों को साक्षियों की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करने की तथा धारा 70 में गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 62 पुलिस अधिकारियों पर उक्त सम्मन का निष्पादन कराने का दायित्व अधिरोपित करती है। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 72 में वारण्ट के निष्पादन का दायित्व भी पुलिस अधिकारियों पर अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालयों द्वारा निर्गत किये जाने वाले सम्मन, जमानतीय वारण्ट एवं गैर जमानतीय वारण्ट का समयबद्ध तामीला तथा निष्पादन कराना पुलिस अधिकारियों का दायित्व है।

5. पुलिस अधिकारियों के उपरोक्त दायित्वों के दृष्टिगत ही गृह विभाग के शासनादेश संख्या-यू0ओ0-64/छ:-पु0-9-2022 दिनांक 23.11.2022 द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस थानों की विजिट/निरीक्षण के समय सम्मन/वारन्ट के तामील के स्तर की समीक्षा आवश्यक रूप से करें व कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करें।

14/10

14/10/2023

No. 0158547
Date 14-10-2023

6. गृह विभाग के उपरोक्त स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद भी शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जनपदीय पुलिस अधिकारियों द्वारा शासन की अपेक्षा के अनुरूप सम्मन तामीला के प्रति गम्भीर प्रयासों का अभाव है और उक्त के परिणाम स्वरूप मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में इस संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है, जिस कारण शासन को प्राय: असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।

7. उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विचारण न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन तथा विभिन्न प्रपीड़ात्मक आदेशिकाओं के शीघ्र तामीला तथा निष्पादन के सम्बन्ध में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

(i) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं जनपदीय पुलिस प्रभारी गृह विभाग के शासनादेश संख्या-यू0ओ0-64/छ:-पु0-9-2022 दिनांक 23.11.2022 का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(ii) विचारण न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन तथा विभिन्न प्रपीड़ात्मक आदेशिकाओं के शीघ्र तामीला तथा निष्पादन हेतु प्रत्येक कमिश्नरेट व जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

(iii) उक्त नोडल अधिकारी डीजी परिपत्र संख्या-40/2023 दिनांक 10.10.2023 में वर्णित व्यवस्था का पूर्ण एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(iv) अनुश्रवण बैठक (Monitoring Cell Meeting) में आपराधिक मामलों में न्यायालयों के सम्मन तामीला की स्थिति की समीक्षा के संबंध में शासनादेश संख्या-एचसी-76(बी) /छ:-पु0-9-2023 दिनांक 30.08.2023 का पूर्ण एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(v) उत्तर प्रदेश जनरल रूल्स क्रिमिनल के अध्याय 3 के नियम 12 के साथ पठित मा0 उच्च न्यायालय परिपत्र आदेश सी.एल. क्रमांक 42/98 दिनांक इलाहाबाद 20.08.1998 के अनुरूप समस्त न्यायालयों द्वारा अपरिहार्यत: आरक्षित किये जा रहे प्रॉसेस रजिस्टर में वह पुलिस अधिकारी जो सम्मन प्राप्त कर रहा है, उसे उक्त रजिस्टर के सुसंगत कॉलम में स्पष्ट ब्लॉक अक्षरों में अपना नाम और नंबर अंकित कराना होगा, जिससे कि उसका उत्तरदायित्व स्थापित किया जा सके।

(vi) अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन द्वारा कोर्ट मोहर्रिर को विटनेस रजिस्टर रखने तथा उक्त में साक्ष्य अंकित कराने हेतु आये साक्षी तथा उसके माध्यम या अन्यथा ज्ञात साक्षियों के नाम मोबाइल नंबर तथा आधार संख्या दर्ज करने तथा उक्त रजिस्टर का संबंधित अभियोजक तथा वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के माध्यम से अनुश्रवण करने संबंधी परिपत्र निर्गत कर दिया जाय तथा पुलिस मुख्यालय स्तर से भी थाना पैरोकार के पैरवी रजिस्टर में तत्सम्बन्धी कालम को बढ़ाने हेतु परिपत्र निर्गत कर दिया जाए।

(vii) नोडल अधिकारियों द्वारा जनपद की मानीटरिंग सेल की बैठक से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि न्यायालय के प्रॉसेस रजिस्टर व थाना/पुलिस कार्यालय के सम्मन सेल के प्रॉसेस रजिस्टर में तामीला के परिप्रेक्ष्य में भिन्नता तो नहीं है, जिससे मा0 उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरुप न्यायालय से जारी आदेशिकाओं का प्रभावी तामीला सुनिश्चित हो सके।

(viii) मॉनिटरिंग सेल की बैठक के माध्यम से यह सुनिश्चित कराया जाए कि न्यायिक अधिकारी अपने प्रॉसेस रजिस्टर तक अभियोजकों तथा उनके मोहर्रिर को एक्सेस प्रदान करें ताकि न्यायालय, अभियोजन एवं थाने के प्रॉसेस रजिस्टर अद्यतन रखे जा सकें।

(ix) उक्त मॉनिटरिंग सेल की बैठक के माध्यम से सम्मन/वारण्ट में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों को चिन्हित उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा भविष्य में यदि इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो दोषी कार्मिकों तथा सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ साथ उपेक्षावान नोडल अधिकारियों की सूचना पुलिस मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाये।

(x) नोडल अधिकारियों के कार्य की नियमित समीक्षा तथा अनुश्रवण जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(xi) विचारण न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन तथा विभिन्न प्रपीड़ात्मक आदेशिकाओं के तामीला संबंधी विषय आईसीजेएस की जनपद स्तरीय तथा राज्य स्तरीय एपेक्स कमेटी की बैठक में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए ताकि उक्त पर समुचित एवं प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण किया जा सके।

8. अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यायालय की आदेशिकाओं के निष्पादन तथा साक्षियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में शासन स्तर से शासनादेशों के माध्यम से निर्गत निर्देशों का कड़ाई से प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में यदि इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो दोषी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।

2-प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यांण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3-अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4-निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, संस्थान, उत्तर प्रदेश।

5-अपर निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6-समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

7-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

8-समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश।

9-गार्ड फाईल।

OATH COMMISSIONER
High Court
Lucknow

No.....01 5 2544
Date.........14-10-2021

Annexure No-3

14

विजय कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 40/2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांक: अक्टूबर 10 2023

विषयः क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9126/2023 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 14.09.2023 के अनुपालन में सम्मन/वारण्ट तामीला की व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु दिशा-निर्देश —

प्रिय महोदय/महोदय,

क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9126/2023 जितेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 10.07.2023 के अनुपालन में सम्मन/वारण्ट आदि के प्रभावी तामीला हेतु तथा अनुश्रवण हेतु डीजी परिपत्र संख्या-30/2023 के माध्यम से विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये थे। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ। सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश दिनांकित 14.09.2023 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सम्मन/वारण्ट तामीला की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं विधि संगत बनाने हेतु निम्नवत निर्देशित किया गया है—

" This Court in Bhanwar Singh @ Karamvir (supra) had extracted details of relevant provisions of the Cr.P.C. and the Government Orders which nominated the officers responsible for service of summons and execution of coercive measures passed by trial courts. Further this Court also found that the current system of departmental accountability was not only insufficient but virtually non existent. It is enabling the police officers to flout the orders passed by the learned trial courts with a sense of impunity. Various solutions were proposed as well as were discussed in the judgment. However, the affidavit of Director General (Prosecution) also does not reflect consideration of the judgment passed by this Court rendered by this Court in Bhanwar Singh @ Karamvir (supra).

Prima facie the affidavit reflects a new trend and rather disturbing tendency in the U.P. Police force. From the affidavit it appears that the junior officers have been set up as mere scapegoats, while superior officers duly nominated by statute and government orders alike are evading all accountability for failure to perform their statutory duties.

Past traditions of the U.P. Police are glorious. The senior leadership has always led from the front in any time of crisis, and has never avoided responsibilities imposed by law. The affidavit submitted by the Director General (Prosecution) gives an impression that the past traditions are no longer being honored.

This Court would like to reiterate, add and emphasis that the failure of the police authorities to serve summons and execute coercive measures is single most important factor which is contributing to the delay in disposal of criminal trials and is denting the credibility of the judicial process.

No. 01528 SMM
Date 14-10-2023

In this wake, this Court is forced to call for the personal affidavits of Additional Chief Secretary (Home), Government of Uttar Pradesh, Lucknow as well as Director General of Police, Government of Uttar Pradesh, Lucknow on the following issues:

I. The current system of departmental accountability of officials nominated by statutes for service of summons and execution of coercive measures issued by the trial courts has failed.

II. To create an efficacious departmental accountability system where officers nominated by the statute (Cr.P.C. as well as Government Orders from time to time) are held accountable for failures to serve summons and execute coercive measures and the inability to compel appearance of witnesses despite orders of the Court. The aforesaid officers nominated by the statute and the government order for the aforesaid purpose are Executive Magistrate, Superintendent of Police of the districts, Commissioner of Police, as well as Inspector General of Police.

III. The system of accountability in the department will become efficacious only if the performance of officers is also judged on the yardsticks of their ability to serve summons, execute coercive measures issued by the court and compel appearance of witnesses on the dates fixed before the learned trial court.

IV. Penalty for departmental action/penalty for failure to comply with the orders of the Court if the explanation for the same is not satisfactory is also liable to be included if the statutory schemes of summons and enforcement of coercive measures have to be implemented as per law.

V. The Director General of Police as well as Additional Chief Secretary (Home) shall also consider the judgment rendered by this Court in Bhanwar Singh @ Karamvir (supra) and the report of the JTRI while filing their affidavits."

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त आदेश में मुख्य रूप से क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र 16771/2023 भंवर सिंह उर्फ करमवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 24.08.2023 तथा सम्मन/वारण्ट तामीला के सम्बन्ध में वर्तमान आपराधिक विधियों में विद्यमान विधिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुये तद्नुसार सम्मन/वारण्ट का समुचित तामीला किये जाने तथा इस कार्य में उपेक्षावान रहने वाले पुलिसकर्मियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु नियम बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में सम्मन/वारण्ट तामीला को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निम्नवत व्यवस्था की जाती है—

- न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट/नोटिस इत्यादि) के प्रभावी तामीला हेतु प्रत्येक कमिश्नरेट व जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

............3

COMMISSIONER ALLAHABAD
14/10

- प्रत्येक नोडल अधिकारी कार्यालय में विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त सम्मन / वारण्ट को एक केन्द्रीय पंजिका में अंकित करने तथा अंकन के बाद सम्बन्धित को तामीला हेतु प्रेषित करने हेतु डेस्क की स्थापना की जायेगी तथा एक केन्द्रीय रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें प्रतिदिन तामील हेतु प्राप्त होने वाले आदेशिकाओं का विवरण तथा तामीला/अदम तामीला आदेशिकाओं की वापसी अंकित की जायेगी। सम्मन/वारण्ट डेस्क पर आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मी तैनात किये जायेंगे।
- सम्मन तामीला के बाद प्राप्त होने वाली तामीला रिपोर्ट को उसी डेस्क पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा केन्द्रीय पंजिका में अंकित किया जायेगा तथा तामीला रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जायेगी।
- तामील करायी गयी आदेशिकाओं (सम्मन / वारण्ट नोटिस आदि) के अनुपालन में न्यायालय में उपस्थित , परीक्षित साक्षियों का विवरण भी सम्मन / वारण्ट डेस्क द्वारा संकलित की जायेगी तथा समय-समय पर सक्षम स्तर पर समीक्षा की जाये।
- नोडल अधिकारी अपने कार्यालय में स्थापित सम्मन/वारण्ट तामीला पंजिका का आकस्मिक मुआयना करेंगे तथा सम्मन तामीला के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देशित निर्गत करेंगे।
- सम्मन/वारण्टों की तामीला तथा अदम तामीला का पाक्षिक विवरण पत्र तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर अपराध गोष्ठी में नोडल अधिकारी द्वारा सम्मन/वारण्ट की तामीला में शिथिलता बरतने वाले थाना-प्रभारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को संवेदनशील किया जायेगा।
- सम्मन/वारण्ट तामीला डेस्क पर प्रत्येक माह प्राप्त होने वाले सम्मनों/वारण्टों के तामीला या अदम तामीला के सम्बन्ध में एक मासिक विवरण पत्र तैयार किया जायेगा और अवलोकन हेतु नोडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अधिकारी सम्मन/वारण्ट के तामीला में शिथिलता बरतने वाले थाना-प्रभारियों को लिखित रुप से सचेत करेंगे। यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अपने कार्य में यथोचित सुधार नहीं किया जाता है तो तीन माह तक लगातार सम्मन/वारण्ट के तामीला के कार्य में शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारियों एवं उनके अधीनस्थों के विरूद्ध नियमानुसार "कारण बताओ नोटिस" निर्गत करते हुये कार्यवाही की जायेगी।
- जनपद स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक एवं कमिश्नरेट स्तर पर सहायक पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थानों द्वारा किये जा रहे सम्मन/वारण्ट तामीला के कार्य का नियमित अनुश्रवण करेंगे एवं आवश्यक निर्देश निर्गत करेंगे। यदि किसी पर्यवेक्षण अधिकारी के क्षेत्राधिकारिता वाले थानों द्वारा किये जा रहे सम्मन तामीला के कार्य में निरन्तर शिथिलता दृष्टिगोचर होती है तो पर्यवेक्षण अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जायेगा।
- नोडल अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के न्यायालयों से प्राप्त सम्मन/वारण्ट के तामीला हेतु उत्तरदायी होंगे तथा लगातार अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन कर समस्त आदेशिकाओं का समयान्तर्गत प्रभावी तामीला सुनिश्चित करायेंगे।
- नोडल अधिकारियों के कार्य की नियमित समीक्षा जोनल अपर पुलिस महानिदेशक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा की जायेगी एवं आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे। जिन नोडल अधिकारियों के कार्य में निरन्तर शिथिलता परिलक्षित हो उनके सम्बन्ध में सूचना इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

OATH COMMISSIONER ALLAHABAD
14/10

- सम्मन/वारण्टों के प्रभावी तामीला हेतु जो प्रक्रिया डीजी परिपत्र संख्या-30/2023 दिनांकित 16.08.2023 द्वारा निर्धारित की गयी है, उसमें आंशिक परिवर्तन करते हुये अपर पुलिस अधीक्षक के स्थान पर पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, शेष निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने में शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/ रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—</u>

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था/अपराध),उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाऐं), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

OATH COMMISSIONER
High Court, Allahabad

OATH COMMISSIONER
High Court, Lucknow
14/10/2023

No. 01585-44
Date 14/10/2023

AFR

Neutral Citation No. - 2023:AHC:243238

Court No. - 37

Case :- CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 9126 of 2023
Applicant :- Jitendra
Opposite Party :- State of U.P.
Counsel for Applicant :- J.B. Singh
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Ajay Bhanot,J.

Heard Shri J.B. Singh, learned counsel for the applicant and Shri Ashok Mehta, learned Additional Advocate General assisted by Shri Paritosh Kumar Malviya, learned AGA-I for the State.

Personal affidavits filed on behalf of Principal Secretary (Home), Government of U.P., Lucknow and Director General of Police, Government of U.P., Lucknow is taken on record.

This Court in **Criminal Misc. Bail Application No. 16871 of 2023, (Bhanwar Singh @ Karamvir Vs. State of U.P.**) noticed the issues arising in administration of justice in bail jurisdictions. This Court has repeatedly held that bail jurisdiction does not denude the constitutional status of the Court. All issues which create impediments or legal issues that arise during the course of bail hearings and are necessary to be decided for fair administration of justice in bail jurisdiction ought to be decided by the Court hearing the bail application. **Bhanwar Singh**

18

भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0006/00053/01844

To
संजय प्रसाद
Sanjay Prasad
C/O: Rajendra Prasad
50 / 4
Wazeer Hasan Road
Lucknow
Lucknow Uttar Pradesh - 226001
9412220000

Signature valid

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

2487 0738 1367

VID : 9167 1902 3069 3728

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है।
- सुरक्षित क्यूआर कोड/ऑफलाइन एक्सएमएल/ऑनलाइन प्रमाणीकरण का उपयोग करके पहचान सत्यापित करें।
- आधार के सभी रूप जैसे आधार पत्र, पीवीसी कार्ड, ई-आधार और एम-आधार समान रूप से मान्य हैं। 12 अंकों की आधार संख्या के स्थान पर आभासी (वर्चुअल) आधार पहचान (VID) का भी उपयोग किया जा सकता है।
- 10 साल में कम से कम एक बार आधार अपडेट जरूर करें।
- आधार आपको विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं /सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट रखें।
- आधार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्मार्टफोन पर mAadhaar ऐप डाउनलोड करें।
- आधार/बायोमेट्रिक्स को लॉक/अनलॉक करने की विशेषता का उपयोग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करें।
- आधार (पत्र/ नंबर) चाहने वाली संस्थायों को उचित सहमति लेने के लिए बाध्य किया गया है।
- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- Aadhaar is unique and secure.
- Verify identity using secure QR code/offline XML/online Authentication.
- All forms of Aadhaar like Aadhaar letter, PVC Cards, eAadhaar and mAadhaar are equally valid. Virtual Aadhaar Identity (VID) can also be used in place of 12 digit Aadhaar number.
- Update Aadhaar at least once in 10 years.
- Aadhaar helps you avail various Government and Non- Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app on smart phones to avail Aadhaar Services.
- Use the feature of lock/unlock Aadhaar/biometrics to ensure security.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek due consent.

भारत सरकार
Government of India

आधार

Issue Date: 09/08/2012

संजय प्रसाद
Sanjay Prasad
जन्म तिथि/DOB: 23/05/1971
पुरुष/ MALE

2487 0738 1367

VID : 9167 1902 3069 3728

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
द्वारा: राजेन्द्र प्रसाद, 50 / 4, वज़ीर हसन रोड, लखनऊ, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226001

Address:
C/O: Rajendra Prasad, 50 / 4, Wazeer Hasan Road, Lucknow, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226001

2487 0738 1367

VID : 9167 1902 3069 3728

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD
Lucknow 14/10/2023

OATH COMMISSIONER High Court, Allahabad
14/10

No. 12158544
Date 14-10-2023

(supra) noticed the problem of delay in trial being caused by chronic failure of the police authorities to serve summons and execute coercive processes issued by the Court for appearance of witness on appointed dates before the trial court.

This Court vide order dated 14.09.2023 issued certain guidelines. In compliance of this order, the Director General of Police, Government of U.P., Lucknow and Principal Secretary (Home), Government of U.P. have filed their affidavits.

The relevant paragraphs of the affidavit filed by the Principal Secretary (Home) is being extracted hereunder:

"5. That in respect of the directions given by Hon'ble High Court from time to time and specially in 'Bhanwar Singh Case' regarding timely execution of processes issued by the learned trial courts the deponent vide Government Order No. HC-100/6-PO-9-2023 Dated 14.10.2023 has issued the following directions.

i. A Superintendent of Police rank officer has been appointed as a Nodal officer for effective execution of processes (summons/warrants/notices) issued by learned trial courts, in every police Commissionerate/District. In this respect D.G. police circular dated 10.10.2023 will be strictly complied by every Nodal officer.

ii. All District Nodal officers will ensure the strict compliance of DG police circular dated 10.10.2023.

iii. All District Magistrates, Executive Magistrates, District Incharge of police will ensure the compliance of Government Order dated 23.11.2022 issued by Department of Home, Government of Uttar Pradesh, Lucknow

iv. Additional Director General (Prosecution) is directed to issue a

direction regarding maintainability of witness register with 'Court Moharrir', in which name and address, mobile number, Aadhar number of every prosecution witnesses will be mentioned and a direction is also issued to insert a column in the 'Pairavi Register' of concerned Pairokar of Police Station.

v. District nodal officer will ensure that the Public Prosecutor and concerned 'Court Moharrir' will have access to process register of learned trial courts so that police station/ summon cell process register could be matched. A direction to learned trial courts to this effect, by Hon'ble High court, will be required.

vi. As per provision of chapter 3 read with rule 12 of General Rules Criminal as well as circular order C.L Number 42/98 dated 20.8.98 issued by Hon'ble High court the name, designation, mobile number of police official who received the court process will be clearly mentioned in the column of process register of learned trial court, so that his responsibility could be fixed. A copy of Government Order No. HC-100/6-PO-9-2023 Dated 14.10.2023 is annexed as Annexure no.2 to this affidavit.

6. That it is pertinent to submit here that regarding timely execution of processes issued by the learned trial courts the Director General of Police, Uttar Pradesh vide DG Circular No. 40/2023, Dated 10.10.2023 has issued the following directions.

i. A central register will be prepared for entering processes received from different trial courts in the office of the Nodal Officer and a Desk will be established for sending the summon/ warrants for its execution daily processes will be recorded in central register, policeman will be deployed at the process desk.

ii. The service receipt received after service of summons/warrants will be entered in the central register by policeman posted at summon desk and service report will be communicated to the concerned trial court.

iii. In compliance with the processes served, the details of the witnesses present and examined in trial courts will also be complied through summon/warrant desk and it will be reviewed from time to time at the competent officer level.

iv. Nodal officers will weekly examine the Summons/warrants execution register.

v. A monthly statement will be prepared in respect of the service of processes and same will be presented before Nodal officer for

perusal. The Nodal Officer will warn in writing to subordinate Officers and station in charge who are on laxity and after three consecutive months of laxity, so cause notice will be issued against the subordinate Officers and In-charge of Police Station.

vi. At District level Deputy Superintendent of Police/Additional Superintendent of Police and at Police Commissionerate level Assistant Police Commissioners will monitor the service of processes by the concerned police stations under their local jurisdiction and if any laxity will be found Supervisory officers will be accountable.

vii. Every Nodal Officer will be responsible for execution of service of processes (summons / warrants/ notices) under their local jurisdiction.

viii. Work of Nodal Officers will be regularly assessed by Additional Director General of Police (Zonal) and Regional Inspector General of Police / Deputy Inspector General of Police in case of any laxity, he will inform the head quarter of Director General of Police.

ix. As discussed above D.G. Circular no. 30/2023 dated 16.08.2023 has been partially changed as Superintendent of Police will be a Nodal Officer in place of Additional Superintendent of Police. A copy of DG police circular dated 10.10.2023 is annexed as Annexure No. 3 to this affidavit.

8. That this Hon'ble Court time to time observed that non presence of police witnesses in trial court is a main impediment for delaying of criminal trials. It is a issue of great concern, deponent is trying to fix departmental accountability for the timely presence of police personnel/witnesses (i.e. investigation officer etc.) in Criminal trial."

Similarly, the relevant paragraphs of the affidavit filed by the Director General of Police, Government of U.P., Lucknow are extracted hereunder:

"5. That in respect of the directions given by Hon'ble High Court from time to time and specially in 'Bhanwar Singh Case' regarding timely execution of processes issued by the learned trial courts the Principal Secretary (Home), Govt. of U.P. vide Government Order No. HC-100/6-PO-9-2023 Dated 14.10.2023 has issued the following directions:

i. A Superintendent of Police rank officer has been appointed as a Nodal officer for effective execution of processes (summons/warrants/notices) issued by learned trial courts, in every police Commissionerate/District. In this respect D.G. police circular dated 10.10.2023 will be strictly complied by every Nodal officer.

ii. All District Nodal officers will ensure the strict compliance of DG police circular dated 10.10.2023.

iii. All District Magistrates, Executive Magistrates, District Incharge of police will ensure the compliance of Government Order dated 23.11.2022 issued by Department of Home, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.

iv. Additional Director General (Prosecution) is directed to issue a direction regarding maintainability of witness register with 'Court Moharrir', in which name and address, mobile number, Aadhar number of every prosecution wintess will be mentioned and a direction is also issued to insert a column in the 'Pairavi Register' of concerned Pairokar of Police Station.

v. District Nodal officer will ensure that the Public Prosecutor and concerned 'Court Moharrir' will have access to process register of learned trial courts so that police station/summon cell process register could be matched. A direction to learned trial courts to this effect, by Hon'ble High Court, will be required.

vi. As per provision of Chapter 3 read with Rule 12 of General Rules Criminal as well as circular order C.L. Number 42/98 dated 20.08.98 issued by Hon'ble High Court the name, designation, mobile number of police official who received the court process will be clearly mentioned in the column of process register of learned trial court, so that his responsibility could be fixed. A copy of Government Order No. HC-100/6-PO-9-2023 Dated 14.10.2023 is annexed as Annexure No. 2 to this affidavit.

6. That in respect of the directions given by Hon'ble High Court from time to time and specially in 'Bhawar Singh Case' regarding timely execution of processes issued by the learned trial courts the deponent has issued the following directions.

i. A central register will be prepared for entering processes received from different trial courts in the office of the Nodal Officer and a Desk will be established for sending the summon/warrants for its execution daily processes will be

recorded in central register, policeman will be deployed at the process desk.

ii. The service receipt received after service of summons/warrants will be entered in the central register by policeman posted at summon desk and service report will be communicated to the concerned trial court.

iii. In compliance with the processes served, the details of the witnesses present and examined in trial courts will also be complied through summon/warrant desk and it will be reviewed from time to time at the competent officer level.

iv. Nodal officers will weekly examine the Summons/warrants execution register.

v. A monthly statement will be prepared in respect of the service of processes and same will be presented before Nodal officer for perusal. The Nodal officer will warn in writing to subordinate Officers and station in charge who are on laxity and after three consecutive months of laxity, so cause notice will be issued against the subordinate Officers and In-charge of Police Station.

vi. At District level Deputy Superintendent of Police/Additional Superintendent of Police and at Police Commissionerate level Assistant Police Commissioners will monitor the service of processes by the concerned police stations under their local jurisdiction and if any laxity will be found Supervisory officers will be accountable.

vii. Every Nodal Officer will be responsible for execution of service of processes (summons /warrants/ notices) under their local jurisdiction.

viii. Work of Nodal Officers will be regularly assessed by Additional Director General of Police (Zonal) and Regional Inspector General of Police / Deputy Inspector General of Police in case of any laxity, he will inform the Headquarter of Director General of Police.

ix. As discussed above D.G. Circular no. 30/2023 dated 16.08.2023 has been partially changed as Superintendent of Police will be a Nodal Officer in place of Additional Superintendent of Police. A copy of DG police circular dated 10.10.23 is annexed as Annexure No.3 to this affidavit."

The Government Orders and the directions issued by

the Principal Secretary (Home), Government of U.P., Lucknow as well as Director General of Police, Government of U.P., Lucknow extracted herein earlier from now on shall be treated as orders of this Court for purposes of implementation.

The Director General of Police, Government of U.P., Lucknow and other responsible officials shall ensure strict compliance of the directions extracted earlier.

Registers of processes to be maintained under Rule 12 of the General Rules (Criminal) shall be regularly updated by the learned trial courts.

The Judicial Training and Research Institute report submitted by Shri Vinod Kumar Rawat, Director, Judicial Training and Research Institute in regard to expeditious service of summons and execution of coercive measures to compel the appearance of witnesses shall also be examined by the Government.

It needs to be emphasized that non appearance of witnesses is one very critical factor but not the sole cause for delays in trials. Hence, this cause of delay cannot be looked at in isolation to the exclusion of infrastructure which is required for discharge of judicial functions. For a long term and enduring solution, a composite vision has to be adopted and

holistic endeavours have to be made. Mere presence of witnesses in itself will not be sufficient to curtail the delays in the trials. The problem of delayed trials requires that various elements of judicial infrastructure have to grow in tandem with the administrative scheme drawn up by the Uttar Pradesh Police and the State Government for compelling appearance of witnesses.

The Government, other stakeholders as well as the Courts shall strive to meet all corresponding requirements of the Courts; and make endeavours to upgrade infrastructure so that witnesses can be duly examined when they appear before the trial court on the appointed dates.

The directions issued by the Director General of Police, Government of U.P. as well as Principal Secretary (Home) shall be treated as directions of this Court.

Order in Bail Application

This is the second bail application.

By means of the the bail application the applicant has prayed to be enlarged on bail in Case Crime No. 483 of 2020 at Police Station- Dankaur, District- Gautam Budh Nagar under Sections 498A, 304B, 201, 120B IPC and Section 3/4 Dowry Prohibition Act. The applicant is in jail since 08.03.2021.

The applicant is on interim bail granted by this Court by order dated 22.05.2023.

The applicant is entitled to bail for the reasons narrated in the order passed this Court on 22.05.2023.

Let the applicant- **Jitendra** be granted bail in the aforesaid case crime number under the same conditions.

The bail application is allowed.

Government Advocate to send a copy of this order to Director General of Police, Government of U.P. and Principal Secretary(Home), Government of U.P., Lucknow.

The Court appreciates the assistance rendered by Shri Ashok Mehta, learned Additional Advocate General assisted by Shri Paritosh Kumar Malviya, learned AGA-I for the State.

Order Date :- 20.12.2023
Vandit

R.R. No......63.......
Date...19/2/024.........
Legal Cell DGP HQ, Lko.

213/2023

शोक मेहता
वरिष्ठ अधिवक्ता
अपर महाधिवक्ता, उ०प्र०
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

निवास : 276/89/17, (Old-21), म्योर रो
निकट टी०वी० टावर क्रासिं
प्रयागराज-211001
ईमेल : amehtasradvahc@gmail.com
मोबाईल : +91-9415235726
कार्यालय फोन : (0532)-2421291

No. 107 /PSAAG/High Court-Alld **Dated :** Saturday, February 17, 2024

To,

The Director General of Police,
Govt. of U.P. Lucknow.

Ref : Orders passed by the Hon'ble Court in different dates in Criminal Misc. Bail Application No. 9126 of 2023, Jitendra Vs. State of U.P. as well as Criminal Misc. Bail Application No. 16871 of 2023 and Criminal Misc. Bail Application No. 51563 of 2023.

Sub : Effective Execution of Processes issued by learned Trial Courts.

Dear Sir,

In the abovementioned matter, number of times orders were passed and vide order dated 20.12.2023, the Hon'ble Court has made the directions issued by the Director General of Police, U.P. as well as Principal Secretary (Home) to be treated as directions of this Court.

The specific directions of the Court are to upgrade infrastructure so that witnesses can be duly examined when they appear.

Registers of processes to be maintained under Rule 12 of the General Rules (Criminal) shall be regularly updated by the learned Trial Courts.

The following directions from now on shall be treated as orders of this Court for purposes of implementation.

1. Additional Director General (Prosecution) is directed to issue a direction regarding maintainability of witness register with 'Court Moharrir', in which name and address, mobile number, Aadhar number of every prosecution witnesses will be mentioned and a direction is also issued to insert a column in the 'Pairavi Register' of concerned Pairokar of Police Station.

2. District Nodal Officer will ensure that the Public Prosecutor and concerned 'Court Moharrir' will have access to process register of learned trial courts so that police station/ summon cell process register could be matched. A direction to learned trial courts to this effect, by Hon'ble High court, will be required.

DIG (P/G)

ADG/GSO
18/02/24

SP(L)

D.I.G.(P.G.),
DGP HQ
U.P., Lucknow
19.02.24

पुलिस अधीक्षक (वि०प्र०)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उ०प्र०, लखनऊ।

अशोक मेहता
वरिष्ठ अधिवक्ता
अपर महाधिवक्ता, उ०प्र०
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

निवास : 276/89/17, (Old-21), म्योर रो निकट टी०वी० टावर क्रांसि प्रयागराज-211001
ईमेल : amehtasradvahc@gmail.com
मोबाईल : +91-9415235726
कार्यालय फोन : (0532)- 2421291

3. Designation, mobile number of police official who received the court process will be clearly mentioned in the column of process register of learned trial court, so that his responsibility could be fixed.

4. A central register will be prepared for entering processes received from different trial courts in the office of the Nodal Officer and a Desk will be established for sending the summon/ warrants for its execution daily processes will be recorded in central register, policeman will be deployed at the process desk.

5. The service receipt received after service of summons/warrants will be entered in the central register by policeman posted at summon desk and service report will be communicated to the concerned trial court.

6. In compliance with the processes served, the details of the witnesses present and examined in trial courts will also be complied through summon/warrant desk and it will be reviewed from time to time at the competent officer level.

7. Nodal Officers will weekly examine the Summons/warrants execution register.

8. A monthly statement will be prepared in respect of the service of processes and same will be presented before Nodal officer for perusal. The Nodal Officer will warn in writing to subordinate Officers and station in charge who are on laxity and after three consecutive months of laxity, so cause notice will be issued against the subordinate Officers and In-charge of Police Station.

9. At District level Deputy Superintendent of Police/Additional Superintendent of Police and at Police Commissionerate level Assistant Police Commissioners will monitor the service of processes by the concerned police stations under their local jurisdiction and if any laxity will be found Supervisory officers will be accountable.

10. Every Nodal Officer will be responsible for execution of service of processes (summons / warrants/ notices) under their local jurisdiction.

11. Work of Nodal Officers will be regularly assessed by Additional Director General of Police (Zonal) and Regional Inspector General of Police / Deputy Inspector General of Police in case

अशोक मेहता
वरिष्ठ अधिवक्ता
अपर महाधिवक्ता, उ०प्र०
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

निवास : 276/89/17, (Old-21), म्योर रो
निकट टी०वी० टावर क्रांसिं
प्रयागराज-211001
ईमेल : amehtasradvahc@gmail.com
मोबाईल : +91-9415235726
कार्यालय फोन : (0532)- 2421291

of any laxity, he will inform the head quarter of Director General of Police.

12. Superintendent of Police will be a Nodal Officer in place of Additional Superintendent of Police.

13. Additional Director General (Prosecution) is directed to issue a direction regarding maintainability of witness register with 'Court Moharrir', in which name and address, mobile number, Aadhar number of every prosecution witnesses will be mentioned and a direction is also issued to insert a column in the 'Pairavi Register' of concerned Pairokar of Police Station.

The directions as issued by the Principal Secretary (Home) as well as by the Director General of Police, Uttar Pradesh are the directions and orders of the Hon'ble High Court and it is upto the State Government to ensure proper implementation of the same in its letter and spirit.

The matter is urgent so please do the needful forthwith.

Yours sincerely,

ASHOK MEHTA

(ASHOK MEHTA)
Addl. Advocate General, U.P.
High Court, Allahabad.

Copy to :

1. The Hon'ble Advocate General, U.P.
2. The Principal Secretary (Home), Govt. of U.P. Lucknow.
3. The Principal Secretary Law/Legal Remembrancer, Govt. of U.P. Lucknow.

ASHOK MEHTA

(ASHOK MEHTA)
Addl. Advocate General, U.P.
High Court, Allahabad.

Encl :

1. Directions of Hon'ble High Court
2. The judgment and order dated 20.12.2023.

अशोक मेहता
वरिष्ठ अधिवक्ता
अपर महाधिवक्ता, उ०प्र०
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

निवास : 276/89/17, (Old-21), म्योर रो
निकट टी०बी० टावर क्रॉ
प्रयागराज-211001
ईमेल : amehtasradvahc@gmail.com
मोबाईल : +91-9415235726
कार्यालय फोन : (0532)- 2421291

N.B.

The Directions issued by the officials of the State may not remain only a paper work as now the same are the Court's direction for effective implementation.

As far as now the Rules for Video Conferencing for Courts in the State of U.P. 2020 have been enforced with effect from 27.11.2020 and the complete paraphernalia and the infrastructure is available in every Court. Now, the Video Conferencing can help the State witnesses also including the Investigating Officers as well as Doctors including other prosecution witnesses at all states of the judicial proceedings and the proceedings conducted by the Court especially when the required person is at any remote point and Coordinator at both the Court point and the remote point has to ensure that in case of application for appearance, evidence and submission through Video Conferencing is moved, the person is duly examined in accordance with the provisions of Rules for Video Conferencing for Courts in the State of U.P. 2020.

Even the orders of the Hon'ble Court are there with specific directions that the facilities of Rules for Video Conferencing for Courts in the State of U.P. 2020 be used to the hilt so that the precious time and machinery of the State Government may be saved and process of prosecution evidence be expedited.

समय से समन एवं विडियो कान्फ्रेंशिंग से न्यायालय की कार्यवाही हेतु मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश

1. हर जिलें में विट्नेस प्रोसेस सर्विस के सुपरविजन हेतु एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा। यह नोडल ऑफिसर पुलिस अधीक्षक के नीचे का पद नहीं होगा।
2. पूरे जिले का समन, वारन्ट, नोटिस आदि की सर्विस का उत्तरदायित्व नोडल ऑफिसर का होगा।
3. नोडल ऑफिसर्स के कार्य का सतत् आंकलन ए0डी0जी0पी0 के द्वारा किया जायेगा।
4. प्रत्येक कोर्ट मोहर्रिर के पास एक गवाह रजिस्टर होगा।
5. गवाह रजिस्टर पर सभी गवाहों का पूरा ब्यौरा लिखा होगा और एक कॉलम पुलिस स्टेशन के पैरोकार के पैरवी रजिस्टर में भी होगा।
6. न्यायालय के प्रोसेस रजिस्टर में भी पुलिस अफसर के पद और मोबाइल नम्बर आदि की डिटेल लिखी रहेगी।
7. हर जिलें का नोडल ऑफिसर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एवं कोर्ट मोहर्रिर के साथ तारतम्य बनाये रखेगा।
8. एक केन्द्रीय रजिस्टर का बनाया जाना भी आवश्यक है, जिसमें दूसरे जिले से आये प्रोसेस नोटिस की डिटेल्स लिखी जायेगी।
9. बाहर से आने वाले प्रोसेस के लिए एक डेस्क भी बनायी जाये, जिसपर प्रोसेस सर्विस के बाद रसीद का विवरण भी रहे। इसी डेस्क पर प्रोसेस/समन के पश्चात् आये हुये गवाह व उनके न्यायालय द्वारा परीक्षित किये जाने की डिटेल एंट्री भी होनी चाहिए।
10. नोडल ऑफिसर के समक्ष महीने भर में कम से कम एक बार यह संपूर्ण विवरण रखा जाना चाहिए और नोडल ऑफिसर का निरीक्षण हर माह अवश्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कमी के विषय में नोडल ऑफिसर अधीनस्थ अफसरों को सचेत करेगा।
11. उत्तर प्रदेश की सभी न्यायालयों में विडियों कान्फ्रेंसिंग दिनांक 27.11.2020 से लागू है।
12. जब भी प्रोसेस सुदूर स्थल के न्यायालय का है, तब अपेक्षित व्यक्ति अपने जिले के विडियो समन्वय से सम्पर्क करेगा एवं विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही होगी।
13. इस हेतु न्यायालय का समन्वयकर्ता एवं सुदूर स्थल का समन्वयकर्ता निर्बाध विडियो कान्फ्रेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।
14. उपरोक्त दिये गये निर्देशों का पालन अत्यन्त आवश्यक है। इससे समय तथा धन दोनों की बचत होगी और निर्बाधरूप से न्यायालय में कार्यवाही भी हो सकेगी। बारम्बार तारीख न लेने के कारण न्यायालय से सम्बन्धित परेशानियाँ भी नहीं होंगी।
15. उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि यह निर्देश उच्च न्यायालय के निर्देश है तथा इनका न मानना अवहेलना माना जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।